सिंचाई / नीति

2016 से 75 लाख हेक्टेयर को पीएमकेएसवाई - प्रति बूंद अधिक फसल सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया: कैलाश चौधरी

मंत्री ने बताया कि अपनी स्थापना के बाद से, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का लक्ष्य कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है।

फिक्की और इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्मार्ट सिंचाई शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने रेखांकित किया कि अकेले 2016 से उल्लेखनीय 75 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है।

अपनी स्थापना के बाद से, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का लक्ष्य कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है और इसने लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि कवरेज में यह पर्याप्त वृद्धि टिकाऊ कृषि और कुशाल जल प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मंत्री ने भारतीय कृषि में क्रांति लाने में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला। वर्तमान में 3000 से अधिक स्टार्ट. अप कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को पेश करने और नई पद्धतियों को अपनाने में लगे हुए हैं। चौधरी ने सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक हितधारक से पानी की कमी के मुद्दों से निपटने के लिए हाथ मिलाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव फ्रैंक.

https://doi.org/10.52151/aet2023474.1688

Received 23/10/2023 Accepted 08/12/2023

लिन एल खोबुंग ने जोर देकर कहा कि देश के 86 प्रतिशत उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल 50 प्रतिशत, जो कि 140 मिलियन हेक्टेयर है, सिंचित है, यह दर्शाता है कि भारत में सिंचित भूमि का आधा हिस्सा अपने जल संसाधनों के बहुमत का उपभोग करता है, जो अधिक कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई से भारत में अतिरिक्त 69 मिलियन हेक्टेयर को कवर किया जा सकता है। उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई एक उद्योग संचालित योजना है, जो निजी क्षेत्र के समर्थन और नवाचार पर निर्भर है।

इस संबंध में, संयुक्त सचिव ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को शामिल करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इस पहल के गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले ही आशाजनक परिणाम सामने आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रयासों की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए क्लस्टर विकास के लिए विशेष प्रावधान पेश किए गए हैं।

इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रीमियर इरिगेशन एड्रिटेक के एमडी श्रीकांत गोयनका ने एक परिवर्तनकारी समाधान के रूप में सूक्ष्म सिंचाई की क्षमता को रेखांकित

किया। कृषि में उपयोग किए जाने वाले पानी का 50 प्रतिशत से अधिक बचाने में सक्षम, सूक्ष्म सिंचाई किसानों को महत्वपूर्ण बचत– उर्वरक में 30 प्रतिशात और श्रम लागत में 40 प्रतिशत प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अक्सर 50 प्रतिशत से अधिक होती है।

कौशल जयसवाल, सह–अध्यक्ष, फिक्की राष्ट्रीय कृषि समिति और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एमडी, रिवुलिस इरिगेशन इंडिया, ने कृषि में जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण चुनौती पर प्रकाश डाला, और भारत के पानी के उपयोग की तुलना चीन से की। उन्होंने कहा कि भारत 320 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए लगभग 560 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी का उपयोग करता है, जो चीन की तुलना में काफी अधिक है, जो 385 बीसीएम का उपयोग करता है और 571 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करता है।

जयसवाल ने बढ़ती आबादी और घटते जल स्तर की चुनौतियों पर जोर देते हुए, आजादी के समय भारत की प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,000 क्यूबिक मीटर से घटकर आज केवल 1,500 रह जाने की गंभीर कमी पर प्रकाशा डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत की अधिकांशा सिंचाई भूजल पर निर्भर करती है, जो वैर्षिक स्तर पर सबसे अधिक है, जो प्रभावी जलभृत पुनर्भरण की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। सूक्ष्म सिंचाई और स्मार्ट कृषि तकनीकों की वकालत करते हुए, जयसवाल ने इन्हें टिकाऊ और कुशल खेती के लिए परिवर्तनक. ारी समाधान के रूप में जोर दिया, जो कृषि चुनौतियों का समाधान करने और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।